तीन महिला लड़ाकू पायलट सहित 16 को मिला नारी शक्ति पुरस्कार

सम्मान ▶ अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया पुरस्कृत

103 वर्ष की एथलीट और 105 साल में कक्षा चार पास करने वालीं महिलाओं का भी सम्मान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

विविध क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान कर अपना परचम लहराने वाली 16 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया है जिसमें से 15 महिलाओं को राष्ट्रपति ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। तीन महिला लड़ाकू पायलट, 103 वर्ष की एथलीट और 105 वर्ष में साक्षरता मिशन के तहत कक्षा चार की परीक्षा पास करने वाली महिलाएं शामिल हैं जो यह साबित करती हैं कि लगन और प्रयास किसी उम्र के मोहताज नहीं होते।

इस वर्ष देश की 16 महिलाओं को विशिष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है जिसमें 15 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया। केरल के कोल्लम की भागीरथी अम्मा दिल्ली नहीं आ सकीं। समारोह में राष्ट्रपति के अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद थी। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को महिला सशक्तीकरण की दिशा में असाधारण योगदान और विशिष्ट कार्य को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह जितरवाल पायलट हैं जिन्होंने पहली बार 2018 में मिग 21 से अकेले उड़ान भरी है। इसके अलावा, कानपुर की कलावती देवी, पुणे की रश्मी उर्धावरेश, लेह लद्दाख की महिला उद्यमी निलजा वांगमो, झारखंड की चामी मुर्मू, बिहार के मुंगेर की वीणा देवी, चंडीगढ़ की मान कौर, पडाला भूदेवी, कश्मीर की आरिफा जान, उत्तराखंड के देहरादून की पर्वतारोही जुड़वां बहनें ताशी और नुंगशी मलिक, गायिका कौशिकी चक्रवती, 105 साल की भागीरथी अम्मा और 98 वर्ष की कर्तियायिनी अम्मा को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय वायुसेना की फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह को नारी शक्ति पुरस्कार-2019 से सम्मानित किया। यह जांबाज तिकड़ी भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। प्रेट्र

- अवनी चतुर्वेदी ने हैदराबाद स्थित वायुसेना एकादमी से प्रशिक्षण हासिल किया। उन्हें राजस्थान के सूरतगढ़ स्थित 23 नंबर टुकड़ी (पैंथर्स) में नियुक्त किया गया। 2018 में उन्हें प्रोन्नत करके फ्लाइट लेफ्टिनेंट की रैंक दी गई। उन्हें इसी साल बनस्थली विद्यापीठ से डॉक्टरेट का अलंकरण प्रदान किया गया।
- भावना कांत बिहार के दरभंगा में जन्मी हैं। उन्होंने बेंगलुरु के बीएमएस इंजीनियरिंग कालेज से बीई (मेडिकल इलेक्ट्रानिक्स) किया है। उन्हें हरियाणा के अंबाला स्थित स्क्वाड्रन नंबर तीन (कोबरा) में तैनात किया गया। युद्धक पायलट का प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें वर्ष 2016 में कमिशन किया गया।
- आगरा में जन्मी मोहना जितरवाल ने नई दिल्ली स्थित एयरफोर्स स्कूल से पढ़ाई की। उनके पिता प्रताप सिंह भारतीय वायुसेना में वारंट अफसर हैं। उनके बाबा लाडू राम जाट 1948 के भारत-पाक युद्ध में शहीद हुए थे। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
- 103 वर्षीय एथलीट मान कौर ने अपना एथलीट कैरियर 93 वर्ष की आयु में शुरू किया। मिरेकल ऑफ चंडीगढ़ यानी चंडीगढ़ के चमत्कार के नाम से जानी जाने वाली मान कौर ने पोलैंड में हुई वर्ल्ड मास्टर्स एथलीट चैम्पियनशिप में ट्रैक और फील्ड में चार स्वर्ण पदक जीते। फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़ी मान कौर ने वर्ल्ड मास्टर्स गेम और अमेरिकन मास्टर्स गेम में 20 से ज्यादा मैडल जीते हैं।
- कौशिकी चक्रवर्ती हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में पारंगत हैं। 38 वर्षीय गायिका को 15 साल से अधिक का अनुभव है और वह खयाल और ठुमरी गायन शैली की माहिर हैं।
- केरल की 105 वर्षीय भागीरथी अम्मा और 98 वर्षीय कर्तियायिनी अम्मा ने केरल के साक्षरता अभियान का हिस्सा बनते हुए कक्षा चार के स्तर की परीक्षा पास की। कर्तियायिनी ने 98 फीसद अंक हासिल किए। वह कहती हैं कि जब वह सौ साल की होंगी तो दसवीं की परीक्षा देंगी और कंप्यूटर भी सीखेंगी। उन्हें बचपन में अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी।
- आंध्र प्रदेश की पदाला भूदेवी महिला किसानों और ग्रामीण उद्यमियों की रोल मॉडल हैं। उन्होंने आदिवासी कार्यक्रम शुरू करके आदिवासी महिलाओं, विधवाओं को पुडु लैंड के जरिये सामुदायिक संगठन काव्स के तहत आत्मनिर्भर बनाया।

महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए कानून बनाएगा महाराष्ट्र

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र सरकार महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने जा रही है। इसके लिए उद्धव सरकार ने लोगों से सलाह भी मांगी है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रविवार को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्विटर पर एक वीडियो संदेश साझा किया। इसके अनुसार, 'महाराष्ट्र सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए जल्द ही एक कानून लाने जा रही है। इसका उद्देश्य अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। अगर आप इस संबंध में अपनी सलाह देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें।' इसके बाद देशमुख ने मुंबई के मरीन ड्राइव से निकली महिला सुरक्षा रैली में हिस्सा लिया। इस रैली में मुंबई पुलिस की महिला कर्मियों ने भी हिस्सा लिया। देशमुख ने महिला उत्पीड़न की घटनाओं को जल्द से जल्द रोकने संबंधी सरकार के संकल्प को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अपने दमखम से इन बेमिसाल महिलाओं ने हजारों की जिंदगी संवारी, बनीं प्रेरणा

नयी दिल्ली, एजेंसियां : जल संरक्षण से लेकर दिव्यांगों के अधिकार समेत विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली जिन सात महिलाओं ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट की कमान संभाली उनका परिचय खुद प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पेजों पर दिया। पीएम ने इन महिलाओं की उपलब्धियों के वीडियो अपने फेसबुक पेज पर शेयर किये। उनकी उपलब्धियों के साथ उन्होंने हैशटैग 'शी इंस्पायर्स अस' भी लगाया।

फूड बैंक से लोगों की भूख शांत कर रहीं स्नेहा मोहनदास : अपनी मां से प्रेरित होकर स्नेहा मोहनदास ने 'फूड बैंक इंडिया' नामक संगठन से पहल शुरू की है। भूख मिटाने के लिए वह भारत के बाहर के कई स्वयंसेवकों के साथ भी काम करती हैं। महात्मा गांधी से प्रभावित स्नेहा ने पीएम के ट्विटर अकाउंट पर लिखा, हमारी 20 से ज्यादा शाखाएं हैं। हमने अपने काम से कई लोगों के जीवन पर असर डाला है। हमने सामूहिक रूप से भोजन पकाना, खाना पकाने का मैराथन आयोजित किया और स्तनपान जागरूकता अभियान के लिए भी पहल की।

स्नेहा मोहनदास। ट्विटर

बम धमाके से दिव्यांग हुईं मालविका अय्यर बनीं कुशल वक्ता : दूसरी महिला मालविका अय्यर की दास्तान एक जुझारू महिला की संघर्ष गाथा है। सन 2002 में जब वे 13 साल की थीं बीकानेर में एक बम धमाके का शिकार हो गईं। उनके हाथ उड़ गए और एक पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अपनी पीएचडी की थीसिस उन्होंने अपनी एकलौती उंगली से टाइप की है। उन्होंने प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल पर लिखा, हिम्मत हार जाना कभी कोई विकल्प नहीं होता। अपनी सीमाओं को भूलकर विश्वास और उम्मीद के साथ दुनिया का सामना कीजिए। अय्यर एक प्रेरक वक्ता, दिव्यांग कार्यकर्ता और मॉडल हैं। अपने भाषणों से वे संयुक्त राष्ट्र तक अपनी धाक जमा चुकी हैं।

मालविका अय्यर। ट्विटर

आरिफा ने कश्मीर की पारंपरिक कला नमदा को दिया नया जीवन : तीसरी महिला कश्मीर की आरिफा जान हमेशा से कश्मीर की पारंपरिक कला को फिर से जीवित करने के सपने देखती थीं। उनका सपना स्थानीय महिलाओं को सशक्त करना था। उन्होंने लिखा, मैं महिला दस्तकारों की स्थिति देखती थी। उनकी जिंदगी में बहार लाने के लिए मैंने 'नमदा' कला को फिर से जीवित करने का प्रयास किया। जब परंपरा और आधुनिकता का मिलन होता है तो चमत्कार हो सकता है। अपने काम में मैंने इसका अनुभव किया। आधुनिक बाजार के मुताबिक हम लोगों ने अपने उत्पादों को डिजाइन किया है। हम लोगों के साथ जुड़े दस्तकार जो कभी 175 रुपये कमाते थे अब 450 रोजाना तक कमा लेते हैं। आरिफा का कहना है कि अपने पिता और पति की सहायता से ही वह इस मुकाम पर पहुंच पाई हैं। कश्मीर विश्वविद्यालय से कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद उसने दो साल का क्राफ्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। आरिफा का कहना है कि इस प्रोग्राम के अंत में उसे मास्टर प्रोजेक्ट देना था। उसने नमदा को बढ़ावा देने का प्रोजेक्ट बनाया। आरिफा के काम को अमेरिका ने भी सराहा।

आरिफा जान। ट्विटर

कल्पना रमेश ने कहा, जल योद्धा बनिये, पानी बचाइये : चौथी महिला जल संरक्षक कल्पना रमेश ने कहा, योद्धा बनिए लेकिन थोड़े अलग तरह की। जल योद्धा बनिए। उन्होंने कहा, छोटे-छोटे प्रयास बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। पानी को जिम्मेदारीपूर्वक खर्च कर, वर्षाजल संचयन, झीलों को बचाकर, इस्तेमाल पानी का पुनः उपयोग और जागरूकता फैलाकर योगदान किया जा सकता है।

कल्पना रमेश। ट्विटर

महाराष्ट्र की बंजारा कला को पहचान दिलाने में जुटी विजया पवार : पांचवीं महिला विजया पवार महाराष्ट्र के बंजारा समुदाय की हस्तकला को पहचान दिलाने में पिछले दो दशक से अधिक समय से जुटी हुई हैं। इस कम के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने लिखा, मेरे काम में हजारों अन्य महिलाएं मेरी सहायता करती हैं।

विजया पवार। ट्विटर

अब तक चार हजार से अधिक शौचालय बना चुकी हैं कलावती : उत्तर प्रदेश के कानपुर की राजमिस्त्री कलावती देवी अब तक चार हजार से से अधिक शौचालयों का निर्माण कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो पीछे मत देखिए और लोगों की कड़वी बातों की अनदेखी कीजिए। उन्होंने कहा, मैं जिस जगह रहती थी वहां हर तरफ गंदगी थी। लेकिन एक पक्का विश्वास था कि स्वच्छता के जरिये हम स्थिति को बदल सकते हैं। मैंने लोगों को इसके लिए तैयार करने का फैसला किया। अपने दामाद और पति के असमय निधन के बाद से कलावती अपने साथ अपनी बड़ी बेटी और उसके दो बच्चों की देखभाल कर रही हैं।

कलावती देवी। ट्विटर

मशरूम की खेती से हजारों लोगों का जीवन बदल चुकी वीना देवी : बिहार के मुंगेर की रहने वाली वीना देवी कहती हैं, जहां चाह, वहां राह है। उन्होंने मशरूम की खेती की योजना के लिए जगह की कमी को अपने आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने कहा, इच्छाशक्ति से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। मुझे असली पहचान मशरूम उगाकर मिली। मेरी खुशी का तब कोई ठिकाना नहीं था जब मैंने अपने पलंग के नीचे एक किलो मशरूम उगाया था। अपने इलाके में मशरूम महिला के नाम से मशहूर बीना 105 गांवों के हजारों किसानों को मशरूम की खेती के लिए प्रेरित कर उनकी जिंदगी बदल चुकी हैं। वे सात सौ से अधिक ग्रामीण महिलाओं को मोबाइल फोन चलाना सिखा चुकी है। वह कहती हैं कि कोई बड़ी पहल करना कभी आसान नहीं होता है। एक समय था जब मुझे भी यह सब बहुत कठिन लगता था, लेकिन एक बार जब कुछ करने की ठान ली तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे लोगों का सहयोग भी मिला और देखते-देखते हमारे सामूहिक प्रयासों से क्षेत्र पर असर पड़ने लगा। बीना देवी अब आगे अपनी पहल का दायरा बढ़ाना चाहती हैं। वह पीएम मोदी की ओर से मिले यादगार अवसर के बाद नए उत्साह के साथ अपने काम में जुट जाना चाहती हैं।

बीना देवी। एएनआइ

व्यवधान के कारण सिर्फ तीन घंटे बैठ पाई राज्यसभा

नई दिल्ली, प्रेट्र : बजट सत्र के दूसरे हिस्से के पहले हफ्ते में राज्यसभा तीन घंटे से भी कम समय के लिए बैठ पाई। पिछले महीने दिल्ली की सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा की विपक्ष की मांग के चलते उच्च सदन कोई खास कामकाज कर पाने में नाकाम रहा। सदन के निर्धारित साढ़े 28 घंटे में से करीब 26 घंटे व्यवधान के कारण कोई कामकाज नहीं हुआ। सदन की कार्यवाही दिल्ली हिंसा पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे की भेंट चढ़ गई।

तीन हफ्ते के अवकाश के बाद सोमवार को बजट सत्र का दूसरा हिस्सा विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान की मांगों पर चर्चा के लिए बहाल हुआ। अधिकारियों ने बताया कि पहले सप्ताह राज्यसभा महज दो घंटे 42 मिनट के लिए बैठ पाई। सदन व्यवधान और बार-बार स्थगन की वजह से अपना 25 घंटे 48 मिनट गंवा बैठा। इसके अलावा स्थायी समितियों की बैठकों में अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान 50 फीसद सांसद गैरहाजिर रहे। सूत्रों के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस के 57 फीसद सांसदों, भाजपा के 36 फीसद सांसदों, कांग्रेस के 15 फीसद सांसदों और अन्य दलों के 50 फीसद सांसदों ने अनुदान की मांगों पर राज्यसभा की आठ समितियों की किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया।

प्रियंका ने दो करोड़ में राणा को बेची थी राजीव की पेंटिंग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ भाजपा ने कहा, हर वित्तीय गड़बड़ी के तार गांधी परिवार से जुड़ते हैं

यस बैंक संकट को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा ने इस संकट को गांधी परिवार से जोड़ने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री को जिम्मेदार ठहराया है।

दोनों दलों के बीच जुबानी जंग तब शुरू हुई, जब भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने कहा, 'भारत में होने वाली प्रत्येक वित्तीय गड़बड़ी के तार गांधी परिवार से ही जुड़ते हैं। यह चाहे भगोड़े विजय माल्या का मामला हो, जो सोनिया गांधी के टिकटों को अपग्रेड करवाते थे और मनमोहन सिंह तथा तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम तक जिनकी पहुंच थी। इसके अलावा राहुल गांधी ने डिफाल्टर नीरव मोदी की ज्वेलरी शॉप का उद्घाटन किया था। राणा कपूर ने प्रियंका गांधी वाड्रा की पेंटिंग खरीदी।' यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर को मनी लांड्रिंग के आरोपों के तहत ईडी ने गिरफ्तार किया है।

कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को बेबुनियाद बताया। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि प्रियंका गांधी ने एमएफ हुसैन द्वारा बनाई गई अपने पिता की एक पेंटिंग की नीलामी की थी। इसे कपूर ने दो करोड़ रुपये में खरीदी थी। इसके लिए चेक से पेमेंट किया गया था। साथ ही प्रियंका ने यह जानकारी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में भी दी है। इसके साथ ही उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि क्या मालवीय यह बताएंगे कि 2014 के बाद पांच सालों में यस बैंक की लोन बुक में कैसे दो लाख करोड़ की बढ़ोतरी हो गई? सिंघवी ने कहा कि इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी नोटबंदी के बाद हुई है।

कांग्रेस ने थर्ड पार्टी वाहन बीमा और जीवन बीमा की प्रीमियम में प्रस्तावित बढ़ोतरी को भी मुद्दा बनाते हुए सरकार पर हमला बोला है। विपक्षी पार्टी ने इसे लेकर हस्तक्षेप करने की मांग की है। पीएफ की ब्याज दरों में कटौती के प्रस्ताव को लेकर भी सरकार की आलोचना की गई है।

गुजरात के नरोदा गाम दंगे की सुनवाई कर रहे जज का तबादला

अहमदाबाद, प्रेट्र : गुजरात हाई कोर्ट ने वर्ष 2002 के नरोदा गाम दंगे की सुनवाई कर रहे विशेष एसआइटी जज एमके दवे का तबादला प्रधान जिला न्यायाधीश वलसाड के पद पर कर दिया है। इस दंगे में तत्कालीन नरेंद्र मोदी सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री रहीं माया कोडनानी भी आरोपित हैं। यह दंगा गोधरा कांड के बाद हुआ था।

शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, 'अहमदाबाद सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एमके दवे का तबादला वलसाड जिले के प्रधान न्यायाधीश पद पर किया गया है। उनकी जगह पर एसके बक्शी को नियुक्त किया गया है, जो अब तक भवनगर के जिला न्यायाधीश थे।' जज दवे नरोदा गाम दंगे में अंतिम बहस की सुनवाई कर रहे थे। इस मामले में अभियोजन और कई आरोपितों के वकील की जिरह पूरी हो चुकी है। जज दवे के तबादले के बाद अब संभव है कि नए जज को सुनवाई के अंतिम दौर की सभी दलीलें नए सिरे से सुननी पड़ें। कोर्ट ने इस मामले में फरवरी 2018 से बयान दर्ज करने शुरू किए थे।

बच्चा गोद लेने के लिए पत्नी की सहमति और समारोह का आयोजन जरूरी : कोर्ट

माला दीक्षित, नई दिल्ली

▶ शीर्ष अदालत ने कहा, शर्तें पूरी न हुई तो दत्तक को नहीं मिलेंगे कानूनी अधिकार

▶ शीर्ष अदालत ने खारिज की संपत्ति में हिस्सा मांग रही लड़की की याचिका

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण कानून में बच्चा गोद लेना तभी वैध माना जाएगा जबकि गोद लेने के लिए कानून में जरूरी बताई गई दो शर्तें पूरी हुई हों। एक तो गोद लेने में पत्नी की सहमति हो और दूसरे गोद लेने के लिए बच्चे के लेन-देन का समारोह हुआ हो। कोर्ट ने गोद लेने की प्रक्रिया और समारोह साबित न कर पाने पर दत्तक बेटी होने का दावा करते हुए संपत्ति में हिस्सा मांग रही लड़की की याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव व दीपक गुप्ता की पीठ ने गत 6 मार्च को दिए गए फैसले में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर मुहर लगाते हुए संपत्ति में हिस्सा मांग रही बेटी एम. वनजा की अपील खारिज कर दी। इससे पहले हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने भी इसी आधार पर वनजा की याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि वनजा ने दत्तक बेटी होने का दावा करते हुए स्कूल प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज पेश किये थे जिसमें संरक्षक की जगह उसके माता पिता का नाम लिखा था। लेकिन कोर्ट ने ये दलीलें नहीं मानी और साफ कहा कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण कानून 1956 में वैध दत्तक प्रक्रिया के लिए दी गई शर्तें पूरी होनी चाहिए। 1956 का कानून कहता है कि गोद लेने की कोई भी प्रक्रिया तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जबतक गोद लेने में पत्नी की सहमति न हो और दत्तक प्रक्रिया यानी बच्चा लेने-देने का समारोह न हुआ हो।

इस मामले में वनजा का कहना था कि जब वह छोटी थी तभी उसके माता-पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी मौसी एम सरला देवी और उनके पति नरसिम्हुलू नायडू ने अपनी बेटी की तरह उसका पालन पोषण किया। उसके स्कूल व कॉलेज के रिकार्ड यहां तक कि राशन कार्ड आदि में भी उन्हीं का नाम संरक्षक के तौर पर दर्ज है। वनजा का कहना था कि उसने अपनी मर्जी से शादी की थी इसलिए उसके माता पिता उससे शुरू में खुश नहीं थे लेकिन बाद में उन्होंने हैदराबाद के एक होटल में शादी का समारोह भी किया था। नरसिम्हुलू नायडू की 19 अगस्त 2003 मे मृत्यु हो गई। एम सरला देवी उनकी संपत्ति पर एकाधिकारी हो गईं। वनजा का कहना था चूंकि वह दत्तक पुत्री है इसलिए नरसिम्हुलू की मृत्यु के बाद वह संपत्ति में आधा की हिस्सेदार है। जबकि सरला देवी जिसे वह मां बता रही थी, ने याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट में कहा कि उसने और उसके पति ने वनजा का पालन पोषण और अच्छी शिक्षा का इंतजाम जरूर किया है क्योंकि उसके माता-पिता बचपन में ही गुजर गए थे लेकिन उन्होंने वनजा को गोद नहीं लिया। यहां तक कि वनजा की नानी ने भी कोर्ट में यही बयान दिया।

स्थायी समिति की सिफारिश

संसद में पेश रिपोर्ट में सरकार को ग्रामीण, सामाजिक और वित्तीय क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों से जुड़े मंत्रालयों के समूह बनाकर विशेषज्ञता वाले अफसरों की तैनाती की सिफारिश की गई है

मंत्रालयों के क्लस्टर में करें विशेषज्ञ अफसरों की नियुक्ति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ समय से भरे जाएं विभिन्न विभागों में अफसरों के रिक्त पद

▶ सीबीआइ में जांच और अदालतों में सुनवाई पर पड़ रहा है असर

भूपेंद्र यादव फाइल फोटो

सरकार के विभिन्न विभागों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कमी पर चिंता जताते हुए संसद की स्थायी समिति ने प्रशासनिक तंत्र की गुणवत्ता में सुधार के कई उपाय सुझाए हैं। कार्मिक, जनशिकायत और विधि एवं न्याय मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने संसद में पेश रिपोर्ट में सरकार को ग्रामीण, सामाजिक और वित्तीय क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों से जुड़े मंत्रालयों के समूह बनाकर इनमें विशेषज्ञता और खास रुचि रखने वाले अधिकारियों को तैनात करने की सिफारिश की है।

राज्यसभा में भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता वाली 28 सदस्यीय समिति ने सुशासन के लिए कई उपाय सुझाए हैं। समिति ने कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों के 'क्लस्टर' बनाकर इनमें विशेषज्ञता और खास रुचि रखने वाले अधिकारियों को तैनात करने से बेहतर प्रशासनिक नतीजे मिल सकेंगे। फिलहाल देश में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के 1,494 अधिकारियों की कमी है। इसी तरह विभिन्न अदालतों, सीबीआइ, केंद्रीय सतर्कता आयोग, आयकर और केंद्रीय सूचना आयोग में रिक्तियां है, जिन्हें भरने की जरूरत है।

सिविल सेवा कैडर में विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त लोगों की सीधी भर्ती (लेटरल एंट्री) के बारे में समिति ने सुझाव दिया है। इस प्रक्रिया से भर्ती होने वाले अधिकारियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर उच्च स्तर पर प्रमोशन भी दिया जाना चाहिए। समिति ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) में भी विभिन्न स्तरों पर 1,281 रिक्त पदों के बारे में कहा कि इतने अधिक पद खाली होने से जांच के लिए लंबित मामलों की संख्या भी बढ़ेगी। जांच की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। सीबीआइ को 1,386 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट के मुकाबले 802 करोड़ रुपये के बजट आवंटन को समिति ने नाकाफी बताया है। इसने कहा कि पर्याप्त कोष के अभाव में एजेंसी से अपेक्षित नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सरकार और लोक प्रशासन के क्षेत्र में हो रहे वैश्विक परिवर्तन का जिक्र करते हुए समिति ने सिविल सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में ऐसे संशोधन की जरूरत बताई है, जिससे उनकी भावनात्मक समझ और बेहतर हो सके। समिति ने उन्हें नैतिक मूल्यों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने की जरूरत पर जोर दिया है।

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) में भी मानव संसाधन और ढांचागत सुविधाओं के अभाव का जिक्र करते हुए समिति ने 48 हजार मामलों के लंबित होने पर चिंता जताई है। समिति ने सरकार को विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए वर्षों से रिक्त पड़े आरक्षित पदों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाने का सुझाव दिया। समिति ने न्यायपालिका और न्यायिक सेवाओं में भी रिक्त पदों की समस्या को लंबित मामलों से जोड़ते हुए कहा कि 2018 से उच्चतम न्यायालय में आठ फीसद, उच्च न्यायालयों में 29 फीसद और अधीनस्थ न्यायालयों में 21 फीसद मामले लंबित हैं, जो चिंता का विषय है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत 1079 पदों में से 397 (37 फीसद) और अधीस्थ न्यायालयों में पांच हजार से अधिक रिक्त पदों (21 फीसद) को भरने की जरूरत बताई है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी